<u>प्रेस रिलीज़</u>

एमपीजे का समावेशी विकास के मुद्दे पर राष्ट्रिय अधिवेशन जलगाँव में

मुंबई, महाराष्ट्र - मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एमपीजे) भारत में समावेशी विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर रही है।

अधिवेशन का उद्देश्य भारत में मौजूद असमानता और वंचित समुदायों की चुनौतियों को उजागर करना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानता को कम करना, हाशिए पर पड़े समुदायों और व्यक्तियों को सशक्त बनाना, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक भेदभाव को मिटाने के प्रयासों को समर्थन देना, सभी के लिए समान अवसर और जीवनयापन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करना, और वंचित समुदायों, जातियों, धर्मों और लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विकास तक पहुंच को बढ़ावा देना है।

ग़ौर तलब है कि, आर्थिक विकास के बावजूद दुनिया में सबसे अधिक ग़रीब भारत में रहते हैं। इनकी संख्या देश की आधी जनसंख्या से भी ज़्यादा है। लोगों की एक बड़ी संख्या ग़रीबी रेखा से नीचे रहती है। संपन्न होने के बजाए, आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक कठिनाई के कारण बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन चंद लोग विश्वास से परे, अकूत धन संपदा के मालिक बने बैठे हैं, जिनकी दौलत में दिन दुनी रात चौगुनी इज़ाफ़ा होता रहता है। ग़रीब और ग़रीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर। भारत में भूख कि स्थिति गंभीर है। दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक बाल कुपोषण दर, विशेष रूप से वेस्टिंग हमारे देश में ही है। देश की ज़्यादातर आबादी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सेहत कि देखभाल तक पहुँच नहीं है।बेरोज़गारी और ग़रीबी बेक़ाबू है।

एमपीजे का मानना है कि समावेशी विकास भारत के विकास का एक आवश्यक आधार है। जब तक सभी के लिए समान अवसर और परिणाम सुनिश्चित नहीं होता है, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है।

एक विकासशील और ग़रीबी से जूझ रहे भारत से विकसित और ख़ुशहाल भारत बनने की यात्रा समावेशी विकास की नीति पर अमल किए बिना संभव नहीं है। जब तक सभी के लिए समान अवसर और परिणाम सुनिश्चित नहीं होता है, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। संविधान समावेशी विकास, चंद हाथों में दौलत सिमटने को रोकने और सभी को इज्ज़त वाली ज़िन्दगी जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। इन संवैधानिक आदर्शों और गारंटी के बावजूद देश की ज़्यादातर आबादी ग़रीबी और कुपोषण का शिकार है। उनकी क्वालिटी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है।

इसलिए एमपीजे समावेशी विकास के संवैधानिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनजागरण हेतु आगामी 11 फरवरी 2024 को जलगांव, महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज नाट्य संकुल में दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक एक अधिवेशन आयोजित कर रही है। अधिवेशन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी तादाद में आम जन के भाग लेने की अपेक्षा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

आरिफ़ देशमुख, एमपीजे जलगाँव ज़िला अध्यक्ष- 9075011884